जितनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई । माननीय सदस्य जो बिहार के हैं उन लोगों को भी थोड़ी दिलचस्पी बिहार के विकास के काम में लगानी चाहिए तब ही यह काम पूरा हो सकेगा ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Chairman, on behalf of the people of Bihar I would like to record our deep appreciation of the Minister's two observations (1) that he has firmly recognized that Bihar is a power starved State and (2) that he has announced a time-bound programme for the implementation of the Koel Karo project. But, at the same time, I would like to ask, is his enthusiasm shared by his colleagues in the Central Electricity Authority who are the policy-making body and his Ministry, because I suspect that unless cooperation of the entire range of establishment within his purview is with him, there are risks that all kinds of spokes will be put into that? Keeping that in view and appreciating his assertion that there is power shortage in Bihar, of a grave kind, will he, at a the same time, institute steps which will supplement the power supply, that is, more Centrally-sponsored thermal power projects on a time-bound basis, on a priority basis, located in Bihar, and (b) will the transmission, problems of Bihar he 1eken up on a priority basis under the new organization that he has set up?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने अपना एश्योरेंस दे दिया है । सभी पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, वन संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, सारी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं और केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास अगले धर्सडे को यह जा रहा है फिर कैबिनेट में जायेगा । बिहार की शार्टेज को मद्देनजर रखते हुए इस कोयल कारो योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है । जहां तक बिहार का सवाल है इस समय बिहार में प्लांट लोड फैक्टर 29 परसेंट है । ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लोड 23 परसेंट है । पूरे देश में सबसे ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर बिहार में है । इस दुर्गति के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है या नहीं ?

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर : आप क्या करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : मैं यह कहूंगा कि बिहार सरकार के पास 1300 मेगावाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी है और वहां केवल 29 परसेंट प्लांट लोड फैक्टर है । इसके लिए बिहार सरकार ही जिम्मेदार है । जहां तक हमारी सरकार का सवाल है यह सैन्ट्रल सेक्टर में 710 मेगावाट बिजली की योजना को स्वीकृति देने का निर्णय ले लिया है । हमारे इस निर्णय से बिहार सरकार की स्थिति में सुधार होगा

श्री राज मोहन गांधी : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति टेहरी डेन प्रोजेक्ट को मिली है या नहीं और अगर मिली है तो कब मिली है और नहीं मिली है तो क्या पर्यावरण मंत्रालय ने कोई संदेह व्यक्त किये हैं तो वे क्या संदेह हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बड़े विद्वान सदस्य हैं । इसके लिए उन्हें अलग से सवाल करना चाहिए ।

Development of Ajanta and Ellora

204. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: t

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to develop Ajanta and Ellora

tTlhe question was actually asked on the, floor of the House by Shri Vishwasrao Ramrao Patil.

with modern infrastructural facilities

(b) if so, what are the detail; thereof;

(c) whether Government would consider *to* modernise the Aurangabad airport and increase the number of flights; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI M. O. H. FAROOK): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. A project proposal has been received from the State Government of Maharashtra for the development of Ajanta and Ellora Region. The main thrust of the proposed plan is on preservation and conservation of the site and their natural environment. The components of the project are strengthening of tourist infrastructural facilities, improvement in electricity, telecommunication, water supply, sewerage, roads, aerodrome facilities etc.

(c) and (d) The project also includes augmentation of facilities at the Aurangabad airport. As regards the increase in the number of flights, the Indian Airlines has proposed to consider augmenting capacity on Auranffabad-Bombay.

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो जवाब दिया गया है उसमें तो खाली राज्य सरकार से प्रस्ताव आया है, इतना ही कहा गया है, लेकिन क्या केन्द्र ने इसको मान्य कर दिया है या इस पर कोई अमल किया है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है ? 14 सितम्बर, 1990 को एक मीटिंग बुलाई गई थी । क्या उसमें कोई निर्णय लिया गया था, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि व निर्णय क्या थे ? इस उत्तर में उसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है । क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना पर अमल करने का निर्णय लिया है ? इस परियोजना पर कुल लागत कितनी आएगी और इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर द्वारा कितना कितना बोझ उठाने की योजना है, इस बारे में मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करें ।

SHRI M. O. H. FAROOK: Sir, the project submitted by the Maharashtra Government is to the tune of Rs. 195.60 crores. The normal quantum of assistance by the OECF for a project is 85 per cent of the total cost. The remaining 15 per cent has to be met by the Central/State Government. If you want the breakup, I would like to give it to you:

Conservation of monuments	Rs. 3.50 crores.
Preservation and enhancement of region, .	Rs. 3.50 crores.
Aerodrome facilities.	Rs. 7.20 crores.
Roads	Rs. 6.91 crores.
Water supply and sewage.	. Rs. 7.50 crores.
Telecommunication .	Rs. 4.50 crores.
Electricity	Rs. 1.15 crores.
Tourist complexfacilities	Rs. 65.70 crores.
Visitors management system and services .	Rs. 18.40 crores.

The total comes to Rs. 176.36 crores. With additional 12 points for overheads, it comes to about Rs. 195.60 crores.

श्री माधव राव सिंधिया : चेयरमैन महोदय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमें यह प्रस्ताव 19 जुलाई, 1990 को मिला था और इस पर महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ था और सलाह-मशविरे के बाद, विचार-विमर्श के पश्चात् 18 सितम्बर, 1990 को ओ.ई.सी.एफ. को भेज दिया गया । ओवरसीज इकनोमिक कोआपरेशन फण्ड जापान का फण्ड है और उनके साथ अब चर्चा जारी

है । मैं सोचता हूं कि अगस्त में आंकलन करने के लिए वे एक टीम भेज रहे हैं और अक्तूबर तक इस पर निर्णय लेने की पूरी संभावना है ।

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है ?

श्री माधवराव सिंधिया : जब वित्तीय मामले पूरी तरह से तय कर लिये जायेंगे उसके बाद दूसरी औपचारिकताएं जब स्वीकृत होंगी, उसके बाद भेजेंगे ।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, यूनेस्कों द्वारा मान्यताप्राप्त विश्व के जो तेरह सौंदर्य स्थल हैं उनमें अंजता-एलोरा एक है । भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में हर दूसरा पर्यटक मुंबई में उतरता है और अंजता-एलोरा वहां से केवल चार सौ किलोमीटर दूर है । फिर भी दिल्ली, आगरा और राजस्थान इस स्वर्ण त्रिकोण को जब कि लाखों विदेशी पर्यटक देखते हैं, अंजता-एलोरा को हर वर्ष केवल 50 हजार पर्यटक निहारते हैं । प्रचार और सुविधा के अभाव का कोई इससे अधिक प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता है और सरकार का वर्तमान उत्तर भी उसी श्रृखंला की एक कड़ी है । हमने सरकार से यह पूछा ही नहीं था कि महाराष्ट्र सरकार ने आपके पास क्या प्रपोजल भेजे हैं । हमारा मूल प्रश्न यह था कि अंजता-एलोरा का विकास करने के लिये सरकार, मैं महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, केन्द्रीय सरकार क्या करने का विचार रखती है । उन्होंने उत्तर में इतना पढ़ दिया कि महाराष्ट्र से ये प्रस्ताव आये हैं और हम विचार कर रहे हैं । जब कि हमने पूछा ही नहीं कि महराष्ट्र से क्या प्रस्ताव आये हैं और उसमें दस करोड़ रुपये देंगे या दो करोड़ देंगे, कौन कितना देगा, यह हमने नहीं पूछां थां । हमने यह पूछा था कि आप, मैंने कहा कि इस स्वर्ण त्रिकोण को चौंकोना बनाकर लाखों विदेशी पर्यटक वहां आये, इस दिशा में, इस दिशा में जो योजना महाराष्ट्र सरकार की ओर से बने वह दूसरी बात है, लेकिन इसमें केन्द्रीय सरकार की अपनी खुद की क्या कोई योजना है ? इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न यह है और जैसा कि कहा गया कि मुंबई-औरंगाबाद हवाई सेवा शुरू करने का विचार है लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं है और पर्यटन में लगभग यही स्थिति महत्वपूर्ण बनती है । जैसे कि मुंबई से आगरा के लिये कोई सीधी हवाई सेवा नहीं चलती जब कि आधे विदेशी पर्यटक केवल मुंबई में आते हैं । मुंबई से आगरा सीधी हवाई सेवा इसलिये नहीं चलती क्योंकि दिल्ली के होटल वाले वाया दिल्ली उनको आगरा भेजना चाहते हैं, इसलिये वे सीधे आगरा के लिये सेवा नहीं रखते हैं । होटल लाबी का प्रेशर इंडियन एयर लाइंस पर इतना होता है कि

there is no direct flight between Bombay and Agra.

जब कि होना चाहिये । जब कि आधे पर्यटक वहां आते हैं तो वे दिल्ली क्यों आयें उनको तो केवल ताजमहल देखना है । लेकिन उनको दिल्ली आना ही पड़ता है । . . . **(व्यवधान)** . . , मैं आगरा के लिये ही कह रहा हूं । हवाई सेवा अगर दिल्ली की होटल लाबी के प्रेशर से चल सकती है तो अंजता-एलोरा के लिये जो हवाई सेवा है वह औरंगाबाद को क्यों नहीं चल सकती, इन दो विषयों पर मैं सरकार से जानना चाहूंगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, मैं माननीय सस्दय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी लाबी का दबाव इस मंत्रालय पर नहीं है । अगर कोई दबाव है तो बाहर की पार्लियामेंट लाबी का दबाव है जो हमारे ऊपर पड़ता है । **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : यह कहना आसान है । आखिर मुंबई-आगरा सीधी हवाई सेवा क्यों नहीं चलती ?

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय सदस्य नाराज न हों। मैं बड़ी नम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि किसी भी लाबी का दबाव हमारे ऊपर है नहीं । मैं थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में उपलब्ध कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि पर्यटन का जो क्षेत्र है मुख्य जो उसका उत्तरदायित्व होता है वह प्रदेश सरकार का होता है । किन्तु हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाये । इसलिये प्रदेश सरकारों से जो जो योजनायें आती हैं, जो जो प्रस्ताव आते हैं उन पर विचार-विमर्श करके हम पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसी योजनाओं द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाय क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विदेशी और डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे सुन्दर और रमणीक स्थानों को देख पायें। आपने मात्र कुछ हजार पर्यटकों की औरंगाबाद, अंजता-एलोरा जाने की बात कही । मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जनवरी से दिसम्बर 1989 के कैलेंडर एयर में लगभग 4 लाख 58 हजार पर्यटक आये, कुछ हजार नहीं । जहां तक.....

श्री प्रमोद महाजन : विदेशी टूरिस्ट कहां जाते हैं । देश में कितने आते हैं और औरंगाबाद कितने आते हैं ? देश में कितने आते हैं और कितने औरंगाबाद जाते हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : सभापति जी, हम तो चाहते हैं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा हों। मैं सोचता हूं कि उनकी तरफ जितना ध्यान केन्द्रित होना चाहिये था वह नहीं किया गया है । आपने दूसरी बात जो सिविल एविऐशन के बारे में कही मैंने जवाब में कहा है कि पीक सीजन में जो होता है उसमें निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एक अतिरिक्त उड़ान बम्बई से औरंगाबाद चलाई जाये । इस पर विचार किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: He asked about part (c) of the main question in the very beginning.

SHRl MADHAVRAO SCINDIA: Sir it is already mentioned here in the statement.

MR. CHAIRMAN: You have put it on the Maharashtra Government. What are you doing about part (c) of the main question? It says: "Whether Government would consider to modernise the Aurangabad airport and increase the number of flights."

SHRl MADHAVRAO SCINDIA: Sir, I have already mentioned in the statement laid on the Table of the House that the project also includes augmentation of facftities at Aurangabad airport from the Maharashtra Government. We have been discussing it with the Maharashtra Government. The project cost that the Maharashtra Government has included in its report is only Rs. 7.20 crores for the augmentation of Jal-gaon and Aurangabad airports. But according to our.. .

SHRI VIREN J. SHAH; How does the airport... (Interruptions)...

SHRJ MADHAVRAO SCINDIA: Kindly let me finish.

It includes both Jalgaon and Aurangabad. But according to our estimates, the National Airport Authority's estimates, it will cost, something like Rs. 15 crores without the cost of the land. we have already been discussing with the Maharashtra Government about giving us the land free of cost so that we can then consider it further.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, Ajanta—Ellora has been one of the most neglected tourist centres in India today. I think the Japanese team are coming here to meet the Minister day after tomorrow to have a meeting with him. I understand that one of the projects being discussed with them is augmentation of facilities plan at Ajanta and Ellora.

In this connection, the Government of Maharashtra had submitted a proposal for Rs. 200 crores; and already two meetings have been. held. It is in the final stage. But I am surprised from the answer of the Minister which says "It is under the consideration but not in the final stage." The way he had put it...

SHRl MADHAVRAO SCINDIA: Don't put words into my mouth.... *(Interruptions)* ...

SHRI SURESH KALMADI: Then, what have you said?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: I have not said that this is not in the final stage. You are putting words into my mouth.

SHRI SURESH KALMADI: "It is in the final stage", okay, thank you.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: I have not said that it is not in the final stage.

SHRl VIREN J. SHAH: It is in the semi-final stage.

SHRI SURESH KALMADI; Regarding part (c) of the main question, the proposal had just gone from the Maharashtra Tourism Development Corporation to the Government of India for Rs. 9 crores. The National Airport Authority have deputed -it's representatives to Aurangabad to assess the cost. I have got the dates of their visit. According to the Maharashtra Tourism Development Corporation, it will cost about Rs. 9 crores. Now, I believe that the Civil Aviation Ministry does not want this Rs. 9 crores to be spent on our project. They feel that the traffic does not justify Rs. 9 crores to be spent. But this project has already been discussed with the Japanese team and they are agreeable on the package. When the Japanese team is agreeing on giving us the aid. I do not know why the Department of Civil Aviation is saying that we do not require it. They feel that the traffic does not justify it. But after putting forth the Japanese plan of Rs. 200 crores and finalising it, everything will be ready in five years. The tourist traffic will be such that it will require the runway to be strengthened, and facilities to be extended. So, there is a problem today between the Department of Tourism and the De-partmen of Civil Aviation. May I know from the Minister of Tourism whether he will convince the Department of Civil Aviation that this Rs8 crores is required ?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, we are not denying the requi re-men's of Aurangabad. It is a very important tourist centre and we fully understand its importance. So, I don't have to be informed about that. But I would like to tell the hon. Minister that we have already drawn up a plan "for the expansion of the facilities there which as I have said earlier would cost Rs. 15 crores. We would bo looking round to the fund. We will be discussing about the proposal also. But we are wanting approximately 160 acres of land also which we would require free of cost from the Maharashtra Government. We have not received yet a satisfactory reply from them. We are awaiting that response. When we get the response we will certainly consider it. In'fact, quite rightly the Ministry of Tourism even wants to look ahead and even think of B-747 jet landing there. But this is something, of course, which is very futurisit'c. But we understand the importance of Ajanta. '

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति जी, एलोरा और अजन्ता हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है । बम्बई के निकट होने के नाते दूसरे देशों से इसका सीधा संपर्क भी है । आधुनिक सुविधाओं के साथ इसका विकास करने के बारे में सवाल आया है । मैं माननीयमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आधुनिक सुविधाओं के बढ़ने से हमारे देश को जो विदेशी

मुद्रा आदि का लाभ होगा क्या उसका अनुमान सरकार ने लगाया है ?

श्री माधवराव सिंधिया : प्रत्येक स्थान पर जो पर्यटक जाते हैं वे कितनी विदेशी मुद्रा राष्ट्र में लायेंगे और खर्च करेंगे इसमें माइट बाई साइट या टूरिस्ट स्पाट बाई टूरिस्ट स्पाट अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले का उत्पादन

*205. **श्री अनन्त राम जायसवाल** क्या **कोयला** मंत्री 15 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतांराकित प्रश्न सं० 29 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपना 1990–91 के वर्ष का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) 1990–91 के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस दौरान कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने 1991–92 के लिये ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य कम करने का ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Coal production in Eastern Coalfields **Ltd.** (ECL) has been below target for the last **two** years namely **1989-90 and 1990-91** due to exhaustion of reserves in some old mines, inadequate and erratic supply of power and heavy raifs .

The targets and achievements for these years are as follows:

(in Million tonnes)

Year	Target ment	Achieve-
1989-90.	31.90	24.46
1990-91.	29.00	23.47

(c) Production target of 24.50 million tonnes fixed for ECL during 1991-92 is 4.38 per cent higher than the actual achievement during 1990-91.

श्री अनन्त राम जायसवाल : माननीय मंत्री जी ने ईस्टर्न कोल फील्ड में कम कोयले के उत्पादन के तीन प्रमुख कारण बताये हैं । नम्बर एक, कि बिजली ठीक से नहीं मिलती है और पर्याप्त नहीं मिलती, दूसरा यह बताया है कि पुरानी खानों में कोयला खत्म हो गया है और तीसरा, बरसात बताया है। जहां तक हमारी बरसात का सवाल है यह तो पहले भी होती रही है। यह कोई कारण नहीं और उसको ध्यान में नहीं लाना चाहिये, मंत्री जी यह मेरा पहला निवेदन है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस स्थान पर जिन खानों में कोयला कम हो गया है क्या उसी के आस पास नयी कोयले की खानें मौजूद हैं या नहीं ? अगर हैं तो कोयले की भारी कमी को देखते हुये उन पर समय रहते काम क्यों नहीं शुरू किया गया, यह मेरा नम्बर एक सवाल है। दूसरा यह है कि बिजली को रोते हैं कोयले वाले और कोयले को रोते हैं बिजली वाले। दोनों मंत्री जी आमने सामने बैठे हैं तो क्या कोयला मंत्री जी बिजली मंत्री जी से मिलकर कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे उनको मुस्तकिल सप्लाई मिलती रहे ?